

Name of the Paper :

दैनिक भास्कर

Published at :

Delhi

Date :

6 OCT 2020

डीडी डायरेक्ट अभी नहीं होगा पेड

नई दिल्ली | दूरदर्शन की डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा डीडी डायरेक्ट को पेड करने की योजना फिलहाल अटक गई है। दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवा में अक्टूबर तक कुछ नए पेड चैनल जोड़ने पर विचार कर रहा था। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल इस योजना की फाइनल मंत्रालय में अटकी हुई है। पेड चैनल जोड़ने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए डीडी डायरेक्ट के सिस्टम को अपग्रेड किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। लेकिन, मंत्रालय से अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। सूत्रों ने बताया कि डीडी डायरेक्ट के बुके में 10 नए पेड चैनल जोड़ने की तैयारी चल रही है। यह प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद थी। लेकिन, इसके लिए मंत्रालय की सहमति जरूरी है।

रेल मंत्रालय में

आकाशवाणी
की अनदेखी

प्रसारण सचिव ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से की शिकायत

शिरिर सोनी | नई दिल्ली

निजी एफएम चैनलों में समाचारों की धूम और विभिन्न टीवी चैनलों की बाढ़ ने लगता है प्रसार भारती के समाचार प्रभाग को गहरी 'चोट' पहुंचाई है। यही कारण है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की सेहत सुधारने की कमान प्रसार भारती के भरोसे न छोड़कर सूचना और प्रसारण सचिव रघु मेनन ने खुद संभाल लिया है। इन दिनों वे ऐसे मंत्रालयों की समीक्षा करने में जुटे हैं जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर को 'भाव' नहीं देते।

इसी क्रम में पहला नंबर आया है रेल मंत्रालय का। रेल मंत्रालय के आला-अधिकारियों ने खबरों की दुनिया से वर्षों पुराने साख और पहुंच वाले ऑल इंडिया रेडियो को अपनी फेहरिस्त से चलता सा कर दिया तो सूचना एवं प्रसारण सचिव रघु मेनन ने इसे 'दिल पर' ले लिया। उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एसएस खुराना को बाकायदा पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कटाक्ष करते हुए लिखा है- 'निजी टीवी चैनलों की आपाधापी में कुछ मंत्रालय अपनी पॉलिसी और कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार में ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विस डिवीजन की सहायता नहीं ले रहे।

उन्होंने लिखा है, 'ऑल इंडिया रेडियो की देश भर के कोने-कोने में पहुंच को देखते हुए एक्सक्लूसिव खबरों के प्रसारण में उनकी मदद की जानी चाहिए।' सूत्रों ने भी साफ कहा कि जिस मीडिया की तरफ मंत्री का ध्यान रहता है चाहे अनचाहे में सभी को उसी ओर व्यवस्था करनी पड़ती है।

ममता के कार्यकाल में हो रही उपेक्षा

रेलवे बोर्ड के उच्च पदस्थ सूत्रों

वे माना कि

ममता

बनर्जी के

रेलमंत्री

बनने के

बाद

मीडिया से

संबंधित ज्यादातर अधिकारियों

का ध्यान बांग्ला भाषी पत्रकारों,

चैनलों या एफएम की खुशामद

में ही बीतता रहा। यही कारण

है कि वर्षों पुराने साख वाले

आकाशवाणी से खबरों के

प्रसारण पर किसी का ध्यान नहीं

गया। अलबत्ता, लालू प्रसाद के

समय आकाशवाणी को खास

तकजो दी जाती थी।



मगर, रघु मेनन के पत्र के शब्द ये बयां कर रहे हैं वे अब और कुछ सुनना, समझना पसंद नहीं करेंगे। हर हाल में सरकारी तंत्र में रहते हुए सरकारी-मीडिया को उर्वर बनाने में सभी मंत्रालय का सहयोग लेने को वे आतुर नजर आ रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष खुराना को वे न्यूज सर्विस डिवीजन के इतिहास से बवास्ता कराना नहीं भूले। उन्होंने लिखा कि 44 क्षेत्रीय भाषाओं में 650 बुलेटिन रोजाना प्रसारित करने वाले एआईआर को भी महत्व दिया जाना चाहिए। और तो और अपने पत्र के साथ खुराना को उन्होंने एआईआर के 48 सेंट्रों के फोन नंबर युक्त कॉपी भी नथी कर दी है। गोया कि भविष्य में इन ताकीदों पर अमल करने में कठिनाई न हो।